The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1990

(insertion of new article 38A)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, I introduce the Bill.

THE AGRICULTURAL WORKERS (MINIMUM WAGES AND WELFARE) BILL, 1986—Contd.

डा. रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे "कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी और कल्याण (विधेयक, 1986" के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया, जो कि इस सदन के अनुभवजन्य, प्रगतिशील और निर्भीक सदस्य श्री एन. ई. बलराम जी ने इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है। मैं पुनः अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों पर आता हूं, जो इसमें दिए गए हैं :

> "इस समय कृषि-कर्मकारों को उनके काम की शर्तों, मजदूरी के ढांचे पेंशन और सामाजिक सुरक्षा-संबंधी अन्य उपायों के बारे में किसी भी प्रकार का विधिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। उनकी दशा-दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। उनकी विशाल संख्या तथा राष्ट्रीय समृद्धि में उनके योगदान को देखते हुए अब समय आ गया है कि समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग को हर संभव विधिक संरक्षण प्रदान किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सामयिक विधेयक है। हमारे जो करोड़ों मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं और अपना खून पसीना बहाकर जो उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी तो दूर की बात है, जो श्रम वे करते हैं, उस श्रम का भी वास्तविक मूल्य, जो केन्द्र सरकार द्वारा निधारित मिनिमम वजेज है, नहीं मिलता है, उससे भी नीचे मिलता है। परिणाम यह हो रहा है कि सर्वोच्च सदन में या लोकसभा में कोई भी कानून या विधि हम बनाते हैं, जब वह क्रियान्वयन स्तर पर आता है, जिनके लिए हम कानून बनाते हैं, जिनके लिए प्रावधान करते हैं, कुछ नहीं बल्कि वह जस का तस रहता है केवल कागजों में ही सारी चीजें रह जाती हैं।

इस विधेयक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस समय देश में जो लेबर है, एग्रीकल्चरल लेबर, उनकी संख्या अगर विस्तार में मैं पूरे देश की प्रान्तवाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज बताऊं तो उसमें बहुत समय लगगा, कृ मूल रूप से देश में जितनी एग्रीकल्चरल लेबर हैं उनमें मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर, दो भागों में बांटकर के उनकी संख्या सदन को बताना चाहता हूं। मेन वर्करस 5,54,99,704 हैं और 89,09,748 हैं। इस प्रकार 6,44,09,452 की दोनों की संख्या बनती हैं। जहां करोड़ों इस देश के मजदूर हों और जिसकी आबादी के बल पर हम संसद में आए हों या सरकार में बैठे हो या जन-प्रतिनिधित्व का सुखलाभ हासिल कर रहे हों—चाहे विधान सभाओं में हों, चाहे संसद में हों, चाहे ब्लॉक में हों, चाहे नगर में हों, उनकी दशा को हम सुधार नहीं पा रहे हैं तो इससे बढ़कर के दुख, वेदना और कथनी-करनी के भेद की दूसरी बात नहीं हो सकती।

हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि श्रमिक के रूप में अत्यंत गरीबी, बेबसी अभाव और पशुओं की भांति आज भी जिन्दगी गुजार रहा है। 1981 की जनगणना के अनुसार इनकी उस समय संख्या लगभग साढ़े पांच करोड थी जिसमें बराबर वृद्धि हो रही है, बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। इन कृषि मजदूरों की न कोई यूनियन है न इनका कोई

संगठन है, न संस्था है और न ही कोई श्रम न्यायालय इनके लिए हैं जहां इनकी शिकायत को सुनकर इन्हें न्याय दिया जा सकता हो। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि कोई न कोई श्रम न्यायालय ऐसा बनाएं और उन श्रम न्यायालयों के बीच में और जो हमारे मजदूर हैं, जो डेली वेजिज भी नहीं पा रहे हैं, उनके बीच में सरकार की ओर से कोई न कोई उनका प्रवक्ता बन कर के उन्हें न्याय दिलाए तब आपका वेल्फेयर स्टेट पालिटिक्स वाला आश्वासन सत्य होगा अन्यथा जैसा पहले हम लोग लेबर के लिए करते थे और उन तक नहीं पहुंच पाता था, वही स्थिति आपकी भी होगी। सदियों से गांव के सेठ-साहूकार और सामंत बंधुआ मजदूर के नाम से जो मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, जो अभाव में पल रहे हैं, जिनकी जिन्दगी दाने-दाने के लिए, वस्त्र के टुकड़े के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा की रोशनी दिलाने के लिए तड़प रहे हैं, उन मजदूरों की पूरी जवानी बंधुआ मजदूरों के रूप में गुजर जाती है। आप मंत्री महोदय बिहार के रहने वाले हैं और एक-एक मील, दो-दो मील के खेतिहर हैं और वे हजारों की संख्या में मजदूरों से खेतों का काम लेते हैं और अगर किसी मजदूर का बच्चा बीमार है, उसकी स्त्री को प्रसव होने वाला है, उसका बेटा अंतिम सांस ले रहा है, तब भी जब जमींदार का मुनीम जाता है और उसको ललकार कर के बाहर निकालता है कि चल खेत में काम करने तो वह सांस टूटते हुए देखता है अपने छोटे से नादान बच्चे की। वह अपने बूढ़े मां-बाप को मौत के घाट उतरते हुए देख रहा है। हम इस सदन के लोग उस स्थान पर अपने को रख कर देखें कि जब एक मजदूर के परिवार का कोई व्यक्ति अभावों में जूझता हुआ दवाओं के अभाव में मौत से संघर्ष कर रहा है और उस समय उसे जबर्दस्ती ले जाकर के खेती के काम में जोड़ा जाता है तो इन्सानियत कराह उठती है और मानवता का विद्रूप अट्टहास सारी दुनिया में होने लगता है। उस विभीषिका को हमें दूर करना है। सारी जवानी लड़कपन में, जवानी आने के पहले जो हमारा एग्रीकल्चरल लेबर है, वह बूढ़ा हो जाता है। उसकी जवानी कब आई, कब गई, पता ही नहीं चलता है।

जिन्हें सिर्फ निदाई, गुड़ाई और कटाई के काम के लिए उपयोग में लिया जाता है, उस वर्ग के लोगों में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। इस वर्ग के हितों का सर्वाधिक ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि महिलाएं जहां श्रम करें वहां उस श्रम के बदले उस मातृत्व शक्ति को शोषण मिले, वह देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। हम भारतवासी यह नारा—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:

दुनिया में कितनी बार गूंजा चुके हैं, लेकिन जब तक हम उसको अधिकार नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इस वर्ग के हितों का सर्वाधिक ध्यान रखने की जरूरत है। आज यहां पर जो भी चर्चा हो रही है, उसका मूल उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हितों का ध्यान रखना है। हरिजन, आदिवासी वर्ग में अधिकांश कृषि मजदूर जो खेती पर अपना जीवन यापन करते हैं। गांवों में जब लौनी होती है तो रात भर वे लौनी करते हैं। सवेरे जब वे फसल को लाते हैं तो जमींदार बैठ जाता है और कम से कम वह फसल कटाई की मजदूरी उनको देता है। आज तक कई योजनाएं आईं लेकिन सरकार की इन योजनाओं के ज्ञान का उनको पता नहीं है। उसको इसका ज्ञान कराइए और उनको प्रकाशित करिए। आज उन मजदूरों के चेहरों पर कर्जों की दहशत है। जो थोड़ी बहुत जमीन उनकी है गांव में वह बनियां, जमींदार लिख लेता है और कर्ज पर कर्ज चढ़ते हुए पीढ़ियां गुजर जाती हैं और वह सामंतशाह सिर पर साथ साथ चलता है। आज तक साहूकारों का आकार बहुत बड़ा हो गया है। उससे खेतिहर मजदूरों को बचाइए, तब आपका श्रम मंत्री होना सार्थक होगा। श्रीमन, मैं इन कृषि मजदूरों के बारे में बड़ी नम्रता से कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिन्हें मैं समझता हूं कि आप विचार कर अपनाएंगे। पहला मेरा सुझाव कि इनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए और केन्द्रीय सरकार में जो डेली वेज देते हैं, उससे ऊपर इनकी मजदूरी होनी चाहिए, अन्यथा 5 रु., चार रु. या ढाई रु. पर आप मजदूरी कराना चाहते हैं, तो इससे उनका भला नहीं हो सकता।

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

दूसरा मेरा सुझाव है कि खेतों में काम के घंटे निश्चित किए जाएं । अधिक समय कोई काम करे तो उसको जैसे सरकारी कार्यालयों में ओवरटाइम मिलता है, उसी तरह से उन्हें भी दिया जाए। तीसरा मेरा सुझाव है कि ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी और गरीब तबकों के लिए जो अन्य कार्यक्रम हैं वे चलाएं जाए ताकि उनका सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्थान हो सके। खेतों में काम करने वालों के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से वहां प्रवेश दिया जाए , जैसा कि आपने पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए अनिवार्यता की है, उसी तरह से खेतिहर मजदूरों के बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन देने का प्रावधान किया जाए, तब कुछ हो सकता है ।

मेरा अगला सुझाव यह है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और सूखे की घटनाएं सबसे ज्यादा गरीब लोगों को प्रभावित करती हैं । इसे ध्यान में रख कर इस वर्ग के लोगों के लिए बाढ़ और सूखा राहत कार्यक्रम बनाए जाएं ताकि इस वर्ग के लोगों को विशेष सहूलियत मिल सके। अभी जो राहत दी जाती है उसे भ्रष्ट अफसरशाही खा जाती है । ऐसे पैसे को खाने वाले जेल के भीतर हो तो इसका दूसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा ।

महोदय, गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन बहुत तेजी से हो रहा है और शहरों में भी झुग्गियां-झोंपड़ियां रोज बन रही हैं और इन झुग्गियों के जो ठेकेदार हैं वे बसाने का भी पैसा लेते हैं और हजारों रुपए लेते हैं और जो वर्ग उसमें रहता है वह गांवों में यदि रोजगार के साधन मुहैया किए जाएं तो उनको अपने घर पर ही रोजगार मिल सकता है और शहरों की ओर गांवों से जो पलायन हो रहा है उसे रोका जा सकता है । अपने गुण के अनुरूप उसको गांव में ही काम मिले, कुटीर उद्योग से काम मिले तो वह अधिक अर्जन कर सकता है ।

श्रीमन्, अंतिम तीन सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । कीटनाशक और रोगनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए मजदूरों के मुंह, आंख, नाक और कान की रक्षा के लिए मास्क पहनने के बारे में उन मजदूरों को जानकारी नहीं होती । इसकी अनिवार्यता आप बना दें । खेत मालिक इसका ध्यान नहीं रखते हैं और उनके फेफड़ों में, उनके वायुरंधों में जहर जाता है और उनका जीवन कम हो जाता है। जब हम फसलों पर छिड़काव करते हैं तो खेत मालिकों का ध्यान इस ओर भी दिलायें और गंभीर बीमारियों का सामना जो मजदूरों को करना पड़ता है उन्हें निःशुल्क इलाज दिलाइये और मास्क पहनने का कानून बना दीजिये आप । और जो जमीन का मालिक है उसको मास्क देना पड़ेगा और बीमार होगा तो निःशुल्क चिकित्सा करानी पड़ेगी, यह मेरा सुझाव है । गांव में मुर्गी पालन, मछली पालन केन्द्र आदि बना कर इनमें कृषि मजदूरों को आप रोजगार भी दे सकते हैं । दुर्घटना आदि के होने पर इन्हें मुआवजा देने का स्थाई प्रबंध भी करें आप। मजदूर पिसता है और पिस करके जो उत्पादन करता है उस उत्पादन पर हम सुख-सुविधायें और आनन्द का भोगमय संसार बसाते हैं और जो उत्पादन करता है आप वर्क टू राईट का प्रस्ताव ला रहे हैं । आपके भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री श्री देवी लाल ने कहा है कि शहरों की सम्पत्ति पर सीलिंग लगायी जाये जैसे 18 एकड़ की सीलिंग आपने लगायी उसी तरह सीमा से अधिक कोई सम्पत्ति न रखें । अगर आपकी सरकार में दम है जितने पूंजीपति बड़े-बड़े हैं, जो अट्टालिकायें खड़ी किये हुये हैं, एक धन की सीमा निर्धारित करिये और इसकी शुरूआत होनी चाहिये। Charity begains at home

प्रधान मंत्री जी की जो जमीन राम जानकी ट्रस्ट और दहिया ट्रस्ट की है वह पूरी दान करें और जो लेबर मजदूर हैं, जो कृषि मजदूर हैं उनमें वितरित किया जाये और उनके माध्यम से सारे देश के जो राजा, महाराजा, सामन्त और

पूंजीपति हैं उनकी नाजायज सम्पत्ति को लेकर के गरीबों में बांट दी जाये तब एक क्रांति आयेगी और जो लेबर मजदूर हैं, एग्रीकल्चरल लेबर जो हैं वह सोचेगी कि आपकी सरकार ने कुछ किया है । राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो ऐश महल इलाहाबाद में है वह भी गरीबों के लिये लेबर का एक सेंटर बनाया जाये उत्तर प्रदेश का उसे एग्रीकल्चरल लेबर का । अंत में निराला की इन पंक्तियों से मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । लिखा तो भिखारी पर था उन्होंने लेकिन एग्रीकल्चरल मजदूर पर भी उतरता है :

वह आता दो टूक कलेजे के करता

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): You tell the lesson to Dr. Chenna Reddy.

DR. RATNAKAR PANDEY: When I go, I will speak to him. They should also change.

जो लोग भी आवश्यकता से अधिक संपत्ति रखते हैं पूरे देश में चाहे किसी दल में हों, सबको अपनी संपत्ति दान कर देनी चाहिये और वह गरीब एग्रीकल्चरल लेबर में बंट जानी चाहिये । इस तरह का बलराम जी जैसे बुजुर्ग का, अनुभवी आदमी का प्रस्ताव लाना सार्थक है नहीं तो कितने प्रस्ताव इस सदन में आये और वातावरण में गूंज कर रह गये, उन पर कार्यान्वियन नहीं हुआ । मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव कार्यान्वित होगा । इसलिये निराला की इन पंक्तियों के साथ :

वह आता दो टूक कलेजे के करता
पछताता पथ पर

पेट पीठ दोनों हैं मिलकर एक चल
रहा लकुटिया टेक

मुठ्ठी भर दाने को भूख मिटाने को
मुख फटी पुरानी झोली को फैलाता

वह आता दो टूक कलेजे के करता
पछताता पथ पर आता

भिखारी और मजदूर में कोई फर्क नहीं है । भिखारी बिना श्रम के अर्जित करता : और मजदूर अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी दाने-दाने को मोहताज है और देश में जो गरीबों की बहुसंख्या है उसमें एग्रीकल्चरल लेबर की संख्या सबसे ज्यादा है । उनके उत्थान के लिये सामूहिक रूप से पूरे सदन का, पूरे देश का दायित्व है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कर्मएव जयते, सत्यमेव जयते का नारा सही सिद्ध हो, वह केवल अशोक चक्र के नीचे लिखा जाने वाला नारा नहीं हो बल्कि जन-जन के हृदय में स्थापित होने वाला सत्यतव जयते और कर्म एव जयते का नारा सार्थक हो । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं ।

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I wholeheartedly support the Bill brought forward by my hon. friend, Shri N. E. Balaram.

[**The Vice Chairman** (Shri M. A. Baby) *in the Chair.*]

In fact, the Communist parties have been there in the forefront of this struggle to bring about an all-India legislation to protect the agricultural labourers in particular. The question is, it has been long overdue for the last forty-three years and our hon. Member, Dr. Pandey must take note of it. He is insisting for that now. I am very happy to hear him that way. But the point is that for forty-three years, there has been no support for it. The major part of our labour force comes from the rural side and agricultural labourers cover backward class people, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and people from all other castes also. So if this legislation would protect the interests of all castes and all classes, then it is urgently needed. In spite of the repeated promises made by the previous Government, it has not been implemented at all. The question is, some time back, there was a serious suggestion from the Government of India and even from the previous Government that the State Governments should see to it that the agricultural labour was protected and proper legislation like that of Kerala should be

[Shri Moturu Hanumantha Rao]

brought forward by every State. That was the recommendation made by the previous Government. But despite the fact that most of the States were ruled by the same party in power, it was not attended to at all. Last year also, I was pressing the Labour Minister to see that the minimum wages are fixed and a Central legislation is brought forward in this House. But what the Labour Minister told us? If I remember correctly, the Labour Ministers conference was held and Labour Ministers from all the States were brought here and a conference took place and in that conference, this question was discussed. Most of the State Labour Ministers were against any immediate legislation being brought. Why? Because they were not at all interested in the down trodden people of our country. Why should the Labour Ministers from the States be consulted? It is because it is a State subject and the Centre had to consult them and verify from them whether all of them would be agreeing to it. But the Labour Ministers coming from most of the States said, let us defer this. So the issue was deferred. Now, I am happy, after this National Front Government came into power and hon. Mr. Paswan ji became the Labour Minister, he has been repeatedly promising to bring about such a legislation. I am very happy to here that, but it should be implemented. That is the question. Though the resolution of our House would be of recommendatory nature to the Central Government, unless the Labour Minister takes it seriously, he cannot bring about such a legislation. He should be rather prompted by this Bill, which would be passed, no doubt, unanimously, in this House, to bring in such a legislation immediately. I hope that the Labour Minister would look into it.

Then the question is, where the agricultural labourers are shelterless, landless, homeless and they are not having any employment for all 365 days. In a year, they get employment for only 150 days or so and even to that extent, proper wages are not paid. The Central Act had been there —the Minimum Wages Act—which was passed in 1948 but the States were to fix up the minimum wakes rates from time to time. They have not doing it properly at all.

4.00 P.M.

And repeatedly, when the organised labour movement was pressing for it, they were, of course, recommending certain rates and those rates were there in the gazette publications, but never implemented at all. Mostly, they were not fair rates and even if they were fair, they were not implemented at all. No committee or established administrative power is there for the implementation of such legislations there. So all these defects are to be taken seriously and then in the coming legislation they have to be attended to. In all calamities, the first casualties would be from the agricultural labour side. I would like to tell you how it is happening. After the recent cyclone, I went to a place where the entire lands were washed off by sea-water. The harvested paddy as well as the heaps were washed off and the landlords or the rich peasants were all helpless in the matter. The agricultural labourers who had come from various districts for harvestation had been working there for 20 days, 15 days like that and they had to gather their income, the minimum wages that were available there. But by the time they were collecting their wages, this cyclone came and uprooted the peasant himself and the labourers. So, due to this suffering, they had no income at all though they worked for 20 to 25 days in the harvesting season. They had to go back to their places, with the help of somebody, without any income being there at all. So, that is the state of affairs for agricultural labourers. Mr. Vice-Chairman, I would draw your attention to another thing. Today, we got a news bit in 'The Hindu' that a boat capsized in the Krishna river. Most of

the 45 passengers that were there were migrating to some other places where there was work. They were agricultural labourers. Most of them, 28 out of 45 passengers who were there in the boat, died. So, as I said, all calamities go against them. They would be the first victims of all calamities, whether it is fire, flood or cyclone. This is the state of affairs so far as agricultural labourers are concerned.

Since such a legislation would cover all castes in this caste-ridden society where every day, some caste feelings are roused and bickerings are developed, the best way of eradicating such things is to see that common measures like this are immediately attended to by the Central Government. So, I would like to appeal to our Labour Minister to attend to it immediately and to see that a proper legislation on the model of the Kerala labour legislation is brought about here. I would also like to draw your attention, Mr. Vice-Chairman, to the fact that where there is a will, there is a way. Since this will had been there in Kerala and in West Bengal, where the communist movements have been strong, they could be implemented there. I ask my hon. friends—I think I can address it to the whole House also—why similar attention was not paid in other States where different parties were ruling, particularly the Congress which was predominantly ruling all over the country and holding most of the States. So...*(Interruption)*.

SHRI A. K. ANTONY (Kerala): Can you yield for a minute? In Kerala, while the Congress and the CPI were ruling the State, a Congress Member was the Labour Minister who introduced this Bill. Do you know that?

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: I am very happy to hear from the Congress benches such an explanation. Do you know, my hon. friend, you did it after a great pressure from the communist movement and the organised labour movement? You have also to depend partly upon the communist movement. It was perhaps under compelling circumstances the Congress (I) also supported it. Therefore, I am happy about this. I also congratulate you to that extent, but the point is that the objective situation should be taken into consideration. What happtned there, why it did not happen in other States where Congress (I) exclusively was ruling, all these things are to be taken into consideration. And I hope thot this Bill is going to be passed by all sections of the House unanimously and I also hope that the hon. Minister of Labour would seriously attend to it and bring about a legislation in this session itself. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABBY): Shri Shiv Pratap Mishra not here.

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, ...

SHRI PRAGADA KOTAIAH (Andhra Pradesh): Sir, I would like to say a few words on this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Let the hon. Member speak. Then there is a list with me. I have to exhaust that. Only then you will be given an opportunity.

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, हमारे साथी बलराम जी ने कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी और कल्याण) विधेयक 1986 जो यहां प्रस्तुत किया है वह अत्यन्त सार्थक, महत्वपूर्ण और उपयोगी है । इसमें इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया हैं कि खेतिहर मजदूर के काम की क्या शर्तें हों, उस मजदूरी का किस प्रकार से प्रारुप हो, ढांचा हो और उन्हें पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधायें किस प्रकार दी जाय । काम की शर्तें, मजदूरी का ढांचा, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन आदि की सुविधायें इन खेतिहर मजदूरों को तभी मिल सकती है जब कि विधि में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जससे इन्हें संरक्षण प्रदान किया जा

[श्री सुरेश पचौरी]

सके और इसी तारतम्य में इस विधेयक पर चर्चा हो रही । मुझे विश्वास है कि हमारे जो मंत्री श्री राम विलास पासवान हैं वे इस संबंध में, जैसा कि उन्होंने मजदूरों के राष्ट्रीय अधिवेशन में आश्वासन दिया था, शीघ्र ही एक विधेयक लायेंगे और अपनी गतिशीलता और कार्यकुशलता का परिचय देते हुये इसी सत्र में इस विधेयक को पारित करवायेंगे ।

मान्यवर, ऐसे श्रमिक जो अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिये पूर्णरूप से या आंशिक रूप से खेती पर आधारित होते हैं उनकी गिनती कृषि श्रमिकों के रूप में की जाती है । मुख्यतः ये खेतिहर मजदूर तीन भागों में विभाजित किये गये हैं । एक तो वे हैं जिनके पास कम खेती है और वे अपने पूरे परिवार का पालन-पोषण उस खेती से नहीं कर पाते हैं और इसके कारण वे किसी जागीरदार के यहां या किसी बड़े किसान के यहां खेती का काम करने जाते हैं । दूसरे प्रकार के कृषि श्रमिक वे हैं जिनके पास बिल्कुल भी खेती नहीं है । और अपने पूरे परिवार का लालन-पालन करने के लिये, पालन-पोषण करने के लिये वह किसी जागीरदार के यहां बड़े किसान के यहां मजदूरी करने के लिये जाते हैं । क्योंकि मैं स्वयं गांव से आया हूं और किसान परिवार से संबंधित हूं और किसान परिवार में भी बड़े मध्यम श्रेणी के किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूं इस नाते इस व्यथा को बड़े अच्छे ढंग से समझ सकता हूं । गांव के श्रमिकों का जो संबोधन इनके साथ किया जा रहा है सही मायनों में उन्हें हरवाहे कहा जाता है । पूरा साल या दो-दो, तीन-तीन साल का अनुबंध किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है कि तुम को तीन साल तक हमारे यहां काम करना होगा और उसके लिये पूरे साल में कुछ गल्ला और कुछ पैसे उन्हें दिये जाते हैं । कुछ पैसे दो या तीन या पांच हजार एडवांस में देकर उन कृषि श्रमिकों को पक्का कर लिया जाता है कि किसी और जमींदार या जागीरदार के यहां उनका अनुबंध न हो पाये । यद्यपि खेती संबंधी काम तो लगभग तीन माह का रहता है लेकिन बाकी मौसम में इन हरवाहों से इन कृषि श्रमिकों से वह काम लिया जाता है जिसकी व्याख्या विस्तार में की जाय तो सहज ही इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि इन लोगों की कितनी दयनीय स्थिति है । न केवल इन कृषि श्रमिकों से काम लिया जाता बल्कि इन कृषि श्रमिकों के परिवार जनों से भी काम लिया जाता है । परिवारजनों से मेरा मतलब यह है कि वे जो सुबह गोबर उठाने का काम होता है गांव में वह गोबर उठाने का काम उस हरवाहे की पत्नी से कराया जाता है जिसको एक या दो या तीन साल के लिये एग्रीमेंट कर के रखा जाता है । जो उस हरवाहे के छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनको गेहूं बीनने के काम में लगाया जाता है और उसके लिये कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक उस जागीरदार या जमींदार की तरफ से नहीं दिया जाता है बल्कि यह माना जाता है कि वह पूरे का पूरा परिवार उसने गिरवी रख लिया है, खरीद लिया है । तो इस विधेयक पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सारे बिन्दुओं पर चर्चा किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है । जहां तक श्रमिकों का सवाल है, दो प्रकार के श्रमिक माने जाते हैं । एक कुशल श्रमिक हैं और दूसरे अकुशल श्रमिक है हैं । कुशल श्रमिक वह माना जाता है जो हल बक्खर का काम करता है, डोर आदि लगाने का काम करता है, बोनी करने का काम करता है, दवाई छिड़कने का काम करता हैं, अफीम का दूध एकत्रित करने का काम करता है । अकुशल श्रमिक वह कहलाता है, कटाई, नंजाई और गहाई आदि का काम करता है जिसमें ज्यादा संख्या महिलाओं की होती है । इन महिलाओं से अकुशल श्रमिकों की हैसियत से वह कठिन से कठिन काम लिया जाता है जो उनसे करवाने की अपेक्षा नहीं की जाती है । काम करने के कोई भी नियत घंटे

तय नहीं हैं। सुबह उठने के वक्त से लेकर रात को सोने के वक्त काम लिया जाता है। जब बोनी का काम होता है हल और बखर चलाने का काम होता है तो रात के समय जब मर्जी होती है तब हल और बखर चलाने का काम प्रारंभ कर दिया जाता है और उसके लिये इनको कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। जब उनको हरवाहे के रूप में एक, दो या तीन साल के लिये तय किया जाता है तो बड़ा किसान यह मान कर के चलता है कि जिन्दगी भर के लिये काम करने के लिये बना लिया गया है इसलिये इस पर विचार किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कृषि श्रमिक होता है मौसम का ध्यान उससे काम करवाते समय नहीं रखा जाता है। काफी गर्मी, सर्दी और बारिश के समय भी उससे काम लिया जाता है। जब हम यह विधेयक ला रहे हैं तो उस समय इस विधेयक को लाते समय इन सारे बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो हमारे यहां कृषि श्रमिकों की संख्या है जो सन 1961 में करीब 3 करोड़ 10 लाख थी वह बढ़कर अब करीब 6 करोड़ 44 लाख हो गयी है। जो निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि कृषि श्रमिकों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और जो हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश माना जाता है जिसमें कि 70 फीसदी से ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं उसमें लगभग 60 प्रतिशत वे लोग रहते हैं जो कि खेतिहर मजदूर हैं। इसलिये इनकी समस्याओं को सुझलाने के लिये यदि समुचित प्रयास भारत सरकार की ओर से कर लिया गया है तो निश्चित रूप से हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारेंगे और भारत देश जिसमें अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं, उसके उत्थान और विकास के लिये कुछ कर सकेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है।

मान्यवर, जो खेतिहर मजदूरों से संबंधित समस्यायें हैं वे प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं, जैसे पहली ऋणग्रस्तता है, पूरे के पूरे खानदान के लिये आज यदि एक कृषि श्रमिक को सेठ साहूकार की तरफ़ से पैसा दिया जाता है तो उसकी इतनी ज्यादा ब्याज दर रहती है कि वह भुगतान नहीं कर पाता है। उसके बच्चे गिरवी रख लिये जाते हैं। फिर उसके बच्चे जब काम करते हैं यदि वे भुगतान नहीं कर पाते तो उनकी अगली पीढ़ी गिरवी रख ली जाती है। अतः इस संबंध में निश्चित रूप से कोई सुधार करने का प्रयास किया जाना चाहिये। जो दासता का जीवन देते हैं उनसे उन्हें मुक्ति दिलाने के लिये कोई न कोई प्रयास करना चाहिये।

जाति पर आधारित जो परम्परा है, ग्रामीण श्रमिकों की समस्या है। उस पर भी विचार करना चाहिये। जो निचली जाति के लोग हैं उनसे अक्सर इस ढंग का काम लिया जाता है। उनकी इस स्थिति का आंकलन करके हमको देखना चाहिये जहां एक तरफ़ वे सामाजिक त्रुटियों के शिकार न हों वहीं दूसरी तरफ़ जातियों के शिकार न हों पायें। इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो ऐसी भूमि जो कृषि योग्य हैं तो वह इन खेतिहर मजदूरों को आवंटित की जाये। हमारे देश में ऐसी बहुत ज्यादा भूमि जो कि अभिचित है लेकिन कृषि योग्य और जिस पर अभी नहीं खेती हो पा रही है और इसके लिये बंधुआ मजदूरों की शिनाख्त स्टेट गवर्नमेंट की एक एजेंसी की तरफ़ से की जानी चाहिये। साथ ही साथ काम करते इन मजदूरों के साथ दुर्घटनायें हो जाती है उनके लिये भी कुछ इंश्योरेंस की स्कीम लागू होनी चाहिये ऐसा मेरा कहना है। इसके लिये, मान्यवर, एक कमेटी का गठन किया गया था। मैं उसकी अनुशंषा पर विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है। जिस सब-कमेटी का गठन किया गया था उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उसकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं उन रिकमेंडेशंस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

[श्री सुरेश पचौरी]

जो सब कमेटी मिनिमम वेजज के लिये बनी थी जिसमें इस बात का प्रावधान था कि सेंट्रल ला फार एग्रीकल्चरल वर्कर्स बनना चाहिये, जब विधेयक को आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो उसमें ज्यादा उम्र वालों के लिये पेंशन की व्यवस्था, महिलाओं के लिये मैटरनिटी बेनीफिट्स, एक्सीडेंटस बेनीफिट आदि इन मजदूरों को मिल सकें, ऐसी व्यवस्था आप करें। उसके लिये ग्रामीण स्तर पर एक लिस्ट बननी चाहिये। उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। जब उनका रजिस्ट्रेशन होगा तो केवल उन्हीं से काम लिया जायेगा और उनके अतिरिक्त किन्हीं और से नहीं लिया जायेगा ताकि उनका शोषण नहीं हो पायेगा। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं उनकी एक यूनियन रहती है और यूनियन के माध्यम से, यदि वे शोषण के शिकार होते हैं तो अपनी आवाज उठा पाते हैं, ऐसे ही इनका रजिस्ट्रेशन हो जायेगा और उसके माध्यम से इनसे काम लिया जायेगा फिर जब उन पर जुल्म-ज्यादती होगी, तांडव नृत्य होगा तो उससे इनको मुक्ति दिलायी जा सकती है। इनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये यदि कृषि मजदूरों की सहकारी समितियां बना दी जायें, और समितियों को जो जो लाभ दिये जाते हैं वे यदि इनको भी मिल सकें तो इससे इनके जीवन स्तर को काफी उठाया जा सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है।

मान्यवर, निश्चित रूप से श्री बलराम जी जो विधेयक लाये हैं वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस विधेयक में जिन जिन बिन्दुओं का समावेश किया गया है यदि उन सब बिन्दुओं को गंभीरता से लाया जायेगा जैसा कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वे शीघ्र ही एक ऐसा विधेयक इस सत्र में लायेंगे, इसमें यदि इन सब बिन्दुओं का समावेश होगा तो निश्चित रूप से खेतिहर मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये कुछ हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman Sir, "Telugu is the language of Telugu people and I am their ruler. One should learn the language to know the beauty of it, which is praised by all the kings and it is the best of all the languages."

This was said by the great literary poet, Emperor of Vijayanagar kingdom Shri Krishna Deva Raya. Though our Telugu language was praised vehmently by the Emperor, I would now speak in English."*

Sir, I whole-heartedly welcome the Agricutural Workers' Bill moved by Shri N. E. Balaram to provide for the payment of minimum wages and for welfare of agricultural workers.

Sir, agricultural workers constitute a major section of the organized labour of our country. They constitute the backbone of the economy of our motherland. But they are the victims of unemployment and under-employment. So a comprehensive legislation for these agricultural workesr is of great importance and urgency because these people are economically exploited and socially suppressed for generations together. There should be a regular revision of minimum wages for agricultural workers. There should be the necessary infrastruclure for effective implementation of the minimum wages.

Sir, in most parts of the country for the greater part of the year the agricultural workers have no work. So there should be a provision for employment guarantee for the agricultural workers. There should be the Employment Guarantee Board at the Centre which provides alternative scheme of employment for these workers. The rural agricultural workers should be dientified because the *bona fide* workers only should get the benefits.

Sir, regarding pension the Government employees, while they are in the tenure of employment, get satisfactory

*English translation of the remarks made in Telegu.

tory wages. After retirement they are getting pension. If they die their widows are getting pension. But regarding agricultural workers, while they are in a position to work they are not in a position to get work. When they are not in a position to work because of their old age, there is nobody to look after them. What a pity! How unfair it is! So the agricultural workers should be provided a pesion scheme after the age of 58 at the date of at least Rs. 300 per month.

Sir, regarding family planning, if a Government employee undergoes tubectomy or vasectomy, that is, permanent methods of sterilisation, they will get Rs. 140 or Rs. 145 per tubectomy and Rs. 125 for a vasectomy. After that hey will get monthly increments. But while coming to the ordinary people, especially agricultural workers, they will get Rs. 120 for vasectomy or Rs. 140 for tubectomy. That's all. They are not getting monthly increments. Why this discrimination? There is nothing more unfair, unjustified or unreasonable in this world than this. These are the people who are going to the fields. They are not getting monthly increments. Those people who are sitting under the fans are getting monthly increments. Why is this so? So this should be equal to all. Either you remove the increments to them or give increments to all other people who undergo the permanent methods of sterilisation, either tubectomy or vasectomy.

Sir, now I come to accidental benefits. The agricultural labour is prone to orthopaedical injury, fractures, dislocation and tetanus. Sometimes they get snake bite or scorpion bite. So, the agricultural labour is prone to accidents. Therefore, accidental benefits should be provided for the agricultural labour. So also maternity benefit. There should be Provident Fund Scheme for them. There should be medical facilities housing facilities and creation of a welfare fund. These schemes should be provided for the agricultural workers.

There should not be discrimination against women in regard to remuneration or wages. There should be safeguards for the protection of child labour in agriculture. Then there should be appropriate advisory and monitoring bodies at the central level, State level and the district level by involving the representatives of the agricultural labour.

Sir, with these few suggestions, I conclude my speech. I support the Bill.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to react to this Bill by Shri Balaram. There are problems in relation to the approach towards the whole agricultural labour in this country. Mr. Balaram is a good friend. The Minister-in-charge and his colleague, the Deputy Minister, are both from my soil. So, I am enthusiastic in supporting them. But I will be less than honest professionally if I gave an unqualified support.

I totally agree with Shri Balaram when he says that the condition of agricultural labour is not good. But I begin to part company with him gradually when his approach is totally protective and welfare oriented rather than promotive. I have rome reasons for that. Firstly, the problems of agricultural labour are not new. They have been there. It is not true that not much has been tried and some achievements made. There has been considerable effort and substantial improvement in the conditions of employment in some regions the level of wages and income for workers. Over the last four decades, we have gathered balance of experience and there should be some learning from that. I submit to the Minister and the House that simple legislation is no progress. That should be one learning because like any other effort towards legislation it may turn out to be a non-event in the sense that you would have voted or the Minister would say that "in due deference to the Mem-

[Prof. Chandresh P. Thakur]

bers I promise that I will bring a comprehensive legislation in the House", Mr. Balaram would withdraw and we would go through the ritual. But the fact of the matter is that it requires a totally revised approach towards the problem of agricultural labour.

First choice is to make it legal, protective and welfare oriented. That is one pack. The other pack is the development of agriculture. Unless you create conditions for more expanded and gainful employment in agriculture through the improvement of the quality of agricultural operation, it will remain a non-event. Thirdly, agriculture on itself will not be able to sustain such a work force. So, we need simultaneous opportunities in the non-farm areas so far as the rural economy of this country is concerned. Essentially, it is related to the larger issue of developmental pattern, the base of development and the quality of that development and opportunities for income and employment emerging out of that. There is the problem of numbers. Very large numbers, 75 million agricultural workers, are there depending on which count you are taking. Maybe it is still an underestimate. The number has to go down. How does the number go down? One is the population rule. But the other rule is shifting of the labour force from agriculture to non-agriculture operations. There is a structural imbalance in the Indian economy. GNP contribution from agriculture is around 30 per cent but the man-power load in the country so far as the agricultural operations are concerned is around 78 per cent. Unless there is transfer of population and a total occupational shift in terms of non-agricultural opportunities for workers, it will be difficult to get the benefits of the kind that the House is looking forward to. The relative question is that it is not employmet, it is not wage employment, but it is a question of number of days of gainful employment. We are averaging at about 100 days' work. China has already achieved 150 and trying 175 days. And it is only when the number is less and the number of gainful employment days out of 365 is substantially improved that the relevance of wage rate comes because finally the income is determined by the supply-demand nexus. Legislation is just a means. Administrative support is one more additional means. Unless the pre-conditions for the laws to be effective are there in a reasonable measure, much of the intent of legislation will remain on the statute book or may be in the hands of the field administrative staff involved with the enforcement of the law. So, Mr. Vice-Chairman, Sir, in agricultural area, I suggest for the consideration of the Minister or Shri Balaram that we cannot run away from the duality of desirability *versus* feasibility. There can be no two opinions that we need to promote the economic and social conditions of the agricultural workers; wherever they are and in whatever conditions they are, they are not very happy But we cannot in our enthusiasm ignore the touch-stone of feasibility. It is there that I submit for your consideration that when we are talking of agricultural labour, we have to talk about three kinds of agricultural labour. One is that which is wage-employed, the other is that which is self-employed. Then the other category of agricultural labour is in occupational over-lap an inherent occupational overlap. People are wage-employed for the part of the time, and for the other part they are self-employed, particularly the marginal farmers. That is the condition because the farms are so limited that they are not able to get sufficient income out of that. As a result, part of the time they work for others. Then the further involved issue is that the members of the marginal agricultural rural family are farm workers also. They are not wage-employed. There is no book-keeping in the domestic budget which shows that 'my wife has contributed so much or my husband has contributed so much, the younger brother or the younger sister has contributed so much.' So, the issues are very complex. Then, if we take one of these packages, the other is the larger farmers, the kulak class or the farmers

who are smaller in size, yet in the green belt area, their conditions are different. The question of capacity to pay is irrelevant there. I totally agree with one of the sub-committees of the Ministrty of Labour's Consultative Committee which has suggested that the minimum wage should not be related to the capacity to pay. It is unrealistic. Nobody can pay more than what he can. It is a fact of life. This does not mean that there are not many employers in the agricultural field who do not have the capacity to pay because the return on investment in agriculture in the green belt area has substantially improved but correspondingly the level of earnings of agricultural labour has not increased. So, there is an element of exploitation there. But so far as the marginal farm is concerned, unless the infrastructure in agriculture, unless the cropping pattern, unless the market support and post-harvest technology and other kinds of things are brought to bear the benefits to their advantage, the secondary effect of giving additional income and employment opportunity to the agricultural worker will not be a feasible step.

Mr. Vice-Chairman, Sir, my submission is that we do not need more laws. We need better laws. We don't only need laws to decorate the statute book or to go on the agenda of the Government or the individual Member saying that 'I promoted so many enactments'. The whole question is: What are you getting out of those Acts? How can we get more out of the existing Acts? Legislation is just a beginning of the story. What kind of administrative support are we providing for the enforcement of that? And what kind of field realities will help or hurt the efforts of the enforcement machinery so far as the enforcement of the agricultural minimum wage is concerned? Sir I have spent large part of my professional lfe looking at the problems of labour. I know there are problems at micro level, there are problems at macro level.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: What about the mechanism?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: I am coming to some of those aspects.

The facts remains that there is variation in agrcultural wages in India, from the highest in Punjab to the lowest, perhaps, in Andhra Pradesh, depending upon which figure you are looking at. The figures which I have shown that in Punjab it is Rs 33.30—this is for the year 1987—whereas it is only Rs. 8/- in Andhra Pradesh. It is a good illustration. Is it that the Andhra Pradesh Government is not able to enforce it? Or, is it that the workers are not asking for it? It is the quality of agricultural operations in Punjab versus the quality of agricultural operations in Andhra Pradesh or Bihar or U.P. that makes all the difference. If you create conditions for the same kind of agricultural operations in other regions like in Punjab, I bet that without any legislation, there will be a marked improvement in the capacity to pay as well as demonstrated improved income levels in the case of agricultural workers in those regions. It is a question of providing corresponding infrastructure support which will tone up the quality of agricultural operations.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I have sat on many wage fixation committees, or, reviewed the workng of legislations in one State or the other in my other capacities. It seems to me that there is scope for some toning up there because the basis is already there in regard to the revision of minimum wages. One is, you take a fixed periodicity; five years, three years. The other is, you relate it to the increase in the cost of living. One of the sub-committee's recommendation is that if there is a 50 point rise in the cost of living index, regardless of the time interval, it should be revised. I suspect that the revision is not taking that course. It is still suffering from administrative intertia in several of the States. It is not taking into consideration the erosion in the purchasing power compared to the last-fixed rate and it is not taking into consideration the urgency to revise it upward in consonance with the increase in the price index so as to restore the real purchasing power in relation to whatever was the rate fixed earlier. This simply means that the administrative

[Prof. Chandresh P. Thakur]

framework within the existing legislation needs to be streamlined and made more functional and more responsive to the ground realities in agricultural operations. (*Time-bell*)

Mr. Vice-Chairman, Sir I would submit again that even with the most realistic wages, the most efficient administrative machinery will feel diffident, if not baffled, when it sees the real situation. What is the real situation? The demand is much less than the supply and this leads to a situation which we all hate, which we all know, but never realise that the minimum that we fix turns out to be, in reality, the maximum in the region. Why? Because it is more than the minimum in the area, because the agriculturist does not have the capacity to pay more than that.

The second thing which takes place is to get the quality of farming improved and if you insist on unrealistic minimum wage, there is a tendency for substituting capital with labour. There is a trend towards mechanisation all over the world. This tendency is there in India also.

Then, if you have unrealistic wages, you are giving power to the enforcement machinery and it is a matter of judgement, or it is a matter of opinion, if you want to be generous to the enforcement machinery; they should try and enforce and we bless them to succeed. But the other part is that they can convert this power not in getting the enforcement of a proper wage, but in extracting a price. This will create a situation which will encourage malpractices among the field staff so far as the administrative machinery is concerned.

The fourth possibility that will arise because of unrealistic wage fixation is the possibility of region-based social and economic conflicts and it will also give rise to a new form of exploitation of agricultural workers. When I say this, let me not be misunderstood. I am not against any improvement in the quality of life, in the working and living conditions and wages of agricultural workers. I am only cautioning 'hasten slowly'. And do not put all your eggs in one basket, that is the legislative basket. Legislation declaration of the intention of the society but much of the work has to be done pre-legislation and post legislation. So, I would submit that in pursuance of the objective to promote the economic life and status of the agricultural worker the Government and the non-Government machinery should consider the possibility of improving the quality of agriculture all along the route, improve the possibility for non-farm employment opportunities and let the workers get organised.

Now, there are some trade union leaders here. Trade unions have always shouted with hoarse voice that they would like to support the weaker and the weakest but in reality their efforts are directed towards serving the interests of those who are better off. Almost all trade unions, regardless of political pursuation, have failed in providing protective umbrella to the agricultural labour not because the need is not paramount but the organisational cost in extending protective umbrella to agricultural labour is much beyond their capability. I would not like to impute motives.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Apply the same measure to all classes.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: What are you suggesting? (*Interruptions*). I am suggesting that in developed region you may enforce whatever legislation you have but in other regions do not create conditions for the non-implementation of the Act.

We know it is difficult to enforce such legislations. We do not need more laws, we need better laws. We do not need laws, we need qualitative improved enforcement of law and enforcement of law is not unrelated to the field rigours, regardless of the administrative rigours that you might provide, the inspectorate staff that you might let loose in the field.

In the end, Mr. Vice-Chairman, I would submit three things. I am all for the betterment of the economic and social life of agricultural workers. Secondly, the conditions of agricultural worker throughout the country are not uniform, not homogenous. There are some regions where agricultural workers are better off and there is scope for their life to be still better off without further legislation, by simply more rigorous enforcement, but there are other parts where the ground reality is so difficult that sheer legislation and toning of the administrative machinery will be very limited or of a limited effect. Therefore, efforts should be directed towards improving the quality of agricultural operations.

The third is, in the ultimate analysis, to provide a better nexus between supply and demand we have to create on an urgent basis extended income and employment opportunities in the non-farm sector so that ultimately we are able to transfer the population pressure from agricultural to non-agricultural area.

The last point is, much of that which needs to be done is known to everybody, to the previous Government and to this Government. It must have been discussed from almost all forums. The very fact that the progress is not being made should alert us that there are some problems. This is not to suggest that more and better efforts should not be made but such efforts should not be devoid of reality. Thank you.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): We know that our nation is an agricultural industry where more than 80 million agricultural labourers are working, that is, 10 per cent of the whole population. And the most miserable thing on their part is that they just get only 60 to 70 days' wages throughout the year. Where there is irrigation they would get not more than 120 days wages. Particularly, the Government had been trying right from the beginning to introduce such a Bill and to enact such laws.

But, unfortunately, it has been pending right from 1986. The Parliament had also constituted some Committees which gave some reports also. But I would like to submit that bonded labour system, particularly in Bihar, U.P. and other parts like Madhya Pradesh, has not been abolished. Still bonded labourers are working there. They do not get their particular wages. And we find this not only among the agricultural labourers, but the Government is doing no better in other fields. In the Postal Department, for example, the Extra-Departmental Agents do not get pension or gratuity. They have to work throughout the day right from eight in the morning to enght in the evening. In the same fashion, the agricultural labour has not been benefited. They do not have a house to live in, clothes to put on and food to eat. Therefore, I would request the hon. Minister to introduce the group insurance scheme for the labourers. The labourers who have worked with one agriculturist or landlord in one season must be employed by them for the nert season also and after attaining the age of 55, they may be given gratuity and pension to live rest of their life. Also some accident benefit must also be given.

For child workers and also for adults, the working must not be for more than six hours with half an hour or one hour rest. Not only that, we have come across many incidents of exploitation in Maharashtra, particularly in Dhule district. In Gujarat

[Shri Gopalsinh G. Solanki]

also, we find exploitation and because of this exploitation, the labour is migrating from one place to another place, from one State to another State, from one district to another district and now we are experiencing the migration of labourer from this nation to countries abroad also. To stop these particular activities, mere passing of legislation will not be enough. There must be implementation of these schemes immediately after the enactment. Then and then alone this particular Act will be very much beneficial from the point of view of the workers.

Thank you very much.

THE AGRICULTURAL WORKERS MENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 20TH AUGUST, 1990

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सूचित करता हूं कि सोमवार 20 अगस्त, 1990 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित कार्य लिया जायेगा :

1. राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 1990 पर आगे विचार और पारित करना ।

2. लोक सभा द्वारा पारित किये गये रूप में महिलाओं के लिये राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 1990 पर विचार और पारित करना ।

3. भारतीय विश्व कार्य परिषद अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और भारतीय विश्व कार्य परिषद विधेयक, 1990 पर विचार और पारित करना ।

4. जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा से संबंधित संकल्प पर चर्चा ।

5. सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा ।

6. लोक सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक, 1990 पर विचार और पारित करना ।

7. कामगारों को प्रबंध में भागीदारी विधेयक, 1990 पर विचार और पारित करना ।

THE AGRICULTURAL WORKERS (MINIMUM WAGES AND WELFARE) BILL, 1986—Contd.

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu)* Mr. Vice-Chairman, Sir, for the last 42 years we have been saying that agriculture is the backbone of our country. But it is regrettable that nothing worthwhile has been done for the betterment of the agricultural workers. While workers engaged in factories and construction of buildings get Rs. 35 to 40 as wage per day, the workers employed in agriculture get only a meagre amount. They get only a pittance like alms.

Hon'ble Member, Shri C.P. Thakur made a very valid point. He said that the wage of agricultural workers should be fixed according to the economic and wage structure of the region. I fully endorse this view. In places where there in less number of workers, the demand is greater and the wage is higher. But in places where the population is high, the workers are more than the demand, hence less wage. This anomoly that is disadvantageous to workers has to be removed. This is possible only if a legislation is brought by the Centre

*English translation of the Original speech delivered in Tamil.